



भ्रष्टाचार के संदर्भ में लोकनायक जय प्रकाश नारायण के विचारों का मूल्यांकन

मनोज कुमार

एम.ए., पी-एच0डी0, समाजशास्त्र विभाग, बड़की डेल्ही-विजय विग्रहा, गया (बिहार) भारत

Received- 25.09.2019, Revised- 28.09.2019, Accepted - 01.10.2019 E-mail: dr.ramnyadav@gmail.com

सारांश : भ्रष्टाचार जे.पी. की प्रमुख चिंताओं में से एक था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इसे समझा या इससे निपटने का प्रयास किया वह उनके उलझे हुए और अव्यावहारिक विचारों और असंगतिपूर्ण या अस्वाभाविक व्यवहार का प्रमुख उदाहरण है। जैसाकि चौथे अध्याय में उल्लेख किया गया है, 1973 के दौरान और 1975 तक, उन्होंने अपने इस विचार को प्रचारित किया कि बढ़ाता हुआ भ्रष्टाचार, जो समाज के सभी वर्गों और भागों में प्रवेश कर चुका था, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसका सामना भारतीय जनता कर रही थी। उन्होंने बार-बार कहा कि यह 'भयानक बुराई' 'हमारे राष्ट्र के मुख्य अंगों को ही दीमक की तरह खोखला कर रही है और उन्होंने इसके उन्मूलन को 'आंदोलन का केंद्रीय बिंदु' 1 बनाया।

कुंजी शब्द – भ्रष्टाचार, चिन्ता, अव्यावहारिक विचार, असंगतिपूर्ण, अस्वाभाविक, उन्मूलन, आन्दोलन।

इसमें कोई संदेह नहीं कि विशेषकर शाही क्षेत्रों एवं मध्यवर्ग में भ्रष्टाचार के मुद्दे ने ही जे.पी. आंदोलन को लोकप्रियता प्रदान की थी। यह भी सच है कि भ्रष्टाचार के चरित्र, कारणों और समाधानों के बारे में जे.पी. की समझ अल्प थी। वे या तो इस तरह के अस्पष्ट व्यान देते थे कि 'भ्रष्टाचार का कारण वह व्यवस्था है जिसने लगभग सभी को भ्रष्ट बना दिया है' 2 जबकि वे अपने अनुयायियों को यह नहीं बताते थे कि 'भ्रष्टाचार उत्पन्न करने वाली व्यवस्था' स्वयं क्या है। या, वे भ्रष्टाचार को राजनीति का प्रतिफलन मानते थे, विशेषकर उन तरीकों और उनकी व्यापकता को लेकर जिसका इस्तेमाल चुनावी या अन्य उद्देश्यों से धन एकत्र करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता था। यदि उन्हें उद्भूत किया जाए, 'फंडों (कोषों) को एकत्र करने का तरीका भ्रष्टाचार के 'वायरस' को राजनीति से कुछ दूसरे क्षेत्रों जैसे व्यवसाय एवं अफसरशाही तक फैला देता है' 3 'राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों के भ्रष्टाचार' से ही वे क्यों आरंभ कर रहे थे, यह प्रश्न उठाते हुए उन्होंने कहा कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं 'क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें वहीं थीं। जनसाधारण के जीवन के सभी आयामों को इस स्रोत ने भ्रष्ट कर दिया है' 4 इसी तरह 'मैं विश्वास करता हूं कि वर्तमान सर्वव्यापी भ्रष्टाचार की जड़ें राजनीति और सत्ता में ही मौजूद हैं' 5

इस संदर्भ में भी, यद्यपि भ्रष्टाचार की राजनीति और सत्ता में मौजूद 'जड़ों' को गहराई और जटिलता के साथ विश्लेषित करने के बजाय, उन्होंने इसे एकपक्षीय मुद्दे के रूप में सीमित कर दिया और सामान्य तौर पर 'कांग्रेस' को तथा व्यक्तिगत तौर पर श्रीमती गांधी को मौजूदा भ्रष्टाचार के लिए पूर्णतः जिम्मेदार लगभग इकलौता स्रोत घोषित कर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि विपक्षी दल

भी पार्टी कोषों के लिए काला धन स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए उन्हें लगभग दोषमुक्त कर दिया कि वे 'परिस्थितियों से विवश होकर ऐसा करते हैं, स्वेच्छा से नहीं। दूसरी ओर, उन्होंने कहा, 'मुख्य हिस्सा हड्डपने की स्थिति में सत्ताधारी पार्टी ही है।' परिणामस्वरूप इस तर्क के बहुत से, और विचित्र उपपरिणाम देखने में आए। चूंकि विपक्षी पार्टियां 'कांग्रेस के असीमित कोषों' से टक्कर ले पाने में अक्षम थीं, वे इस निष्कर्ष पर पहुंची की 'कांग्रेस को चुनावों द्वारा नहीं हटाया जा सकता' और इसलिए उन्हें 'विरोधों, घेरावों, बंदों और हिस्सा का मार्ग अखित्यार करना चाहिए।' बहराहाल, जे.पी. के अनुसार, 'कांग्रेसी सरकारें जनता की मांगों को पूरा किए बिना आधे रास्ते में ही छोड़ देती थीं।' पुनः उन्होंने जोर दिया, 'पार्टी और चुनाव व्यवस्था के लिए, व्यवसायियों से करोड़ों रुपए उगाहने के श्रीमती गांधी के कृत्य, राजनीतिक भ्रष्टाचार का ऐसा उदाहरण है जिसने अधिकतर सत्ताप्रेरी कांग्रेसियों की नैतिक संवेदनशीलता को नष्ट कर दिया है।' पार्टी कोष के लिए धन एकत्र करने की भूमिका, चुनाव में व्यापक स्तर पर धन व्यय करने की प्रवृत्ति इत्यादि को भ्रमवश भ्रष्टाचार के लिए पूर्णतः या अंशतः प्राथमिक रूप से श्रीमती गांधी को जिम्मेदार ठहराने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया।

जे.पी. ने भ्रष्टाचार और सरकार की आर्थिक नीतियों के बीच अति साधारण संबंधी की सृष्टि की: 'यह सत्ताधारी दल के व्यापक कोषों के लिए अदम्य भूख थी जो सिर्फ काले धन से ही बुझ सकती थी और जो एक ओर उत्पादन, वितरण और मूल्य नियंत्रण के लिए बाधक थी तो दूसरी ओर, इन सबकी असफलताओं का भी कारण थी।'

राजनीतिक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जे.पी. का दृष्टिकोण बहुत मनमाना, यहां तक कि अवसरवादी था। ऊपर खंड-3



में उल्लिखित अपने बहुप्रचारित विचारों को, जैसे विपक्षियों समेत सभी पार्टीयां भ्रष्टाचार के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं, अनदेखा करते हुए, और उनसे दूरी बनाए रखने के बजाय उन्होंने बहुत पहले उनसे संबंध बना लिये और उन्हें अपने आंदोलन का भाग बना लिया, बल्कि कुछ पहले उनसे संबंध बना लिये और उन्हें अपने आंदोलन का भाग बना लिया, बल्कि कुछ क्षेत्रों में उन्हें मुख्य बल के रूप में प्रयुक्त किया। न ही उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने धर्मयुद्ध में ऐसे कई राजनीतिक नेताओं—बीजू पटनायक, महामाया प्रसाद, के.हनुमंथेया और हरे कृष्ण महताब का सहयोग लेने में संकोच किया जो भ्रष्ट माने जाते थे और कई न्यायिक आयोगों द्वारा भ्रष्ट घोषित किए जा चुके थे। उन्होंने कई बार जगजीवन राम को अपनी ओर आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने अतिभ्रष्ट डी.एम.के. सरकार की निंदा करने तथा इसके विरुद्ध संघर्ष का आह्वान करने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वह कांग्रेस विरोधी थी और जे.पी. आंदोलन के प्रति मित्रतापूर्ण रुख रखती थी। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका को, अपने मुख्यपत्र एवरीमैंस वीकली को वित्तपोषित करने की अनुमति दी। उनके अपने आंदोलन में सदस्यों के भ्रष्टाचारों के किस्सों को या तो अनदेखा कर दिया जाता था या दबा दिया जाता था, जिनमें सबसे बुरा मामला गुजरात के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल का था जो गुजरात के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के मुख्य लक्ष्य रहे थे। श्रीमती गांधी को वास्तव में विवश किया गया कि वे उनसे इस्तीफा लें। फिर भी जून 1975 के चुनावों के बाद चिमनभाई पटेल के सहयोग से बनने वाली सरकार को जे.पी. ने समर्थन दिया और 1977 के बाद उन्हें जनता पार्टी में भी शामिल कर लिया गया। जून 1974 को जे.पी. को लिखे गए श्रीमती गांधी के पत्र में कुछ दम हैः ‘विडंबना यह है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों का अपने पक्ष में राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग होता है। मेरे पास उदाहरण हैं— मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगी। जो व्यक्ति कांग्रेस में रहते हुए भ्रष्ट थे, वे कांग्रेस से बाहर आते ही स्वच्छ हो गए हैं।’ वास्तव में, कभी जे.पी. ने एक पल के लिए भी रुककर विचार नहीं किया कि वे भ्रष्ट लोगों की संगत में या उन्हीं की मदद से भ्रष्टाचार से युद्ध कैसे कर सकते हैं। उनकी एकमात्र टिप्पणी थी कि ‘या तो भ्रष्ट व्यक्तियों को निकाल बाहर किया जायेगा’ या आंदोलन की मांगों के दबाव से ‘ऐसे व्यक्ति भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएंगे।’

जे.पी. ने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए किन उपायों को सुझाया? जैसाकि अगस्त 1974 में हिंदुस्तान टाइम्स से एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा, ‘सुझाव देने के लिए स्वयं मेरे पास कुछ विशेष नहीं है।’ इसके बजाय उन्होंने उन सुझावों का उल्लेख किया जो भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न समितियों ने दिए थे— संथानम समिति, वांचू आयोग, प्रशाससनिक सुधार आयोग, दल-बदल विरोधी समिति इत्यादि। उन्होंने व्यापक वैधानिक अधिकारों से युक्त, केन्द्र में ‘लोकपाल’ की नियुक्ति और राज्यों में ‘लोकआयुक्त’ की नियुक्तियों का भी जोरदार समर्थन किया। उन्होंने इस सुझाव का भी समर्थन किया कि विधायिका के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति के विवरण देने चाहिए। इससे आगे ताजे अंकड़ों पर आधारित समाधान खोजने के लिए, जे.पी. ने विशेषज्ञों से राय लेने की बात की कि उनसे ज्यादा ठोस और प्रभावी कदम उठाने को कहा जाए। हम जानते हैं कि इन आयोगों और समितियों की अधिकतर अनुशंसाएं, जिन्हें जे.पी. ने समर्थन दिया था, 1975 के बाद बनने वाली सरकारों द्वारा वैधानिकता प्राप्त कर चुकी थीं लेकिन राजनीतिक या प्रशाससनिक रूप से उनका कोई नतीजा नहीं निकला था और आज शायद उससे ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है।

जो भी हो, ये सभी दीर्घ अवधि वाले कदम थे। लोगों को तुरंत क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि उन्हें जमाखोरों और भ्रष्ट अधिकारियों के सामने प्रदर्शन तथा भ्रष्ट मंत्रियों, राजनीतिज्ञों के विरुद्ध जनता में जाग्रत्त लानी चाहिए। उन्हें भ्रष्ट अधिकारियों और व्यापारियों के खिलाफ सत्याग्रह और धेराव तथा उनका बहिष्कार करना चाहिए। यहां तक कि निर्धारक स्तर पर उत्तरकर उन्होंने कहा, ‘भ्रष्ट मंत्रियों, अधिकारियों, व्यवसायियों और बड़े किसानों के बेटों-बेटियों को 12 घंटों का उपवास रखते हुए भ्रष्टाचार एवं समाज विरोधी कार्य त्यागने के लिए उन पर दबाव बनाना चाहिए। फिर छात्रों को यह प्रण करना चाहिए कि वे भ्रष्ट कार्यवाहियों में कभी लिप्त नहीं होंगे।’

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. जयप्रकाश नारायण, पी.डी., सं.6, पृ.104
2. एलेन एंड वेंडी स्कार्फ, जे.पी. हिज बायोग्राफी, 1977 पुनर्मुद्रित, पृ.422 पर उद्धृत
3. जयप्रकाश नारायण, टी.आर., सं.3, पृ.21
4. जयप्रकाश नारायण, सं.23, पृ.23
5. जयप्रकाश नारायण, टी.आर., सं.3, पृ.127